ISSN–2278-5655

AMIERJ Peer Reviewed Journal

AARHAT MULTIDISCIPLINARY INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH JOURNAL

Volume–X, Issues– V Sep – Oct 2021

"भारतीय शिक्षा में निजीकरण एवं वैश्वीकरण के युग में विद्यालय का बदलता परिदृश्य"

अखिलेश यादव

सहायक आचार्य

शिक्षा विभाग,म० गां० अ० हि० वि० वर्धा

सारांश :-

प्रस्तुत शोध पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि 20 वीं शताब्दी का 21 वीं शताब्दी में संक्रमण वैश्वीकरण {globalisation } , उदारीकरण { liberalisation }, निजीकरण {privatisation }, बाजारीकरण {commercialisation }, तथा उपभोक्ता संस्कृति { consumer culture} {यद्यपि ये सभी शब्द एक दुसरे के पर्याय हैं } के साथ हो रहा है | ऐसा संक्रमण आज से कई सौ साल पहले भी हुआ था | वह युग उदारवादी विचारधारा में उदय हुआ था | वस्तुत: वह उदारीकरण का प्रारम्भिक समय था | आज वह अपनी एक नयी ऊँचाई पर अमरत्व की घोषणा के साथ प्रकट हो रहा है |निजीकरण के कारण सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों की हालत खस्ता है | शिक्षक संघो के पदाधिकारी तो विद्यालय में हस्ताक्षर करने जाते हैं | विद्यालयों में प्रयोगशाला ,पुस्तकालय आदि अनुपयुक्त हालत में देखने को मिलते हैं | इन सभी स्थितियों से लोगों को यह लगता है कि विद्यालय का निजीकरण हो जाना चाहिए |

भूमिका:-

उदारवाद जिसे हम उदारीकरण के नाम से आज ज्यादा जानते पहचानते हैं। एक विशेष आर्थिक वर्ग उभरते हुए पूंजीवादी वर्ग का दर्शन रहा है। अतः इसका आर्थिक पहलू अधिक

महत्वपूर्ण रहा है। 1760 से1830 ई. की जबरदस्त औद्योगिक क्रांति के दौर में फ्रांस में फिजियो क्रेटर्स, इंग्लैंड में एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस आदि ने **लैजेफर का सिद्धांत** दिया। और आर्थिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार की राजनीति दखलअंदाजी का विरोध करते हुए आर्थिक स्वतंत्रता की सिफारिश की। स्वतंत्र समझौते, व्यापार प्रतियोगिता, अर्थव्यवस्था, बाजार तथा बाजारों समाज को आर्थिक सफलता की आवश्यकता बतलाते हुई आर्थिक मामलों में राज्य के हस्तक्षेप का विरोध किया गया। यह शुद्ध पूंजीवादी आर्थिक सिद्धांत औद्योगिक क्रांति के दौरान पूंजीपति वर्ग के हित की पूर्ति करने वाला तथा स्वतंत्र पूंजीवादी प्रगति की आवश्यकता थी। इसी सिद्धांत ने राज के अधिकार क्षेत्र को सीमित कर आर्थिक मामलों में पूंजीवादी उत्पादन संबंधों को स्वतंत्र रूप से स्थापित किया। इसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना। साथ ही उसके कार्यक्षेत्र को सीमित किया। उसका कार्य क्षेत्र नकारात्मक है, बाहरी आक्रमणों से व्यक्ति की सुरक्षा, आंतरिक अव्यवस्था से व्यक्ति की सुरक्षा तथा कानून के अनुसार किए गए समझौतों का पालन। यह सिद्धांत उस सरकार को सर्वोत्तम मानता है जो कम से कम शासन करें। यह सिद्धांत स्वतंत्रता का अर्थ समस्त सत्ताओं से मुक्ति मानता है। जो कि स्वच्छता का नकारात्मक स्वरूप है।

निजी करण का इतिहास अधिक पुराना नहीं है। इसका इतिहास करीब 50 से 55 वर्ष का है। **privatisation** शब्द **1960 में सर्वप्रथम** प्रयुक्त किया गया। पीटर एफ डूकर ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक the age of Discontinuity में किया, उसके 10 वर्ष बाद **मारग्रेट थैचर इंग्लैंड की प्रधानमंत्री** बनी और उन्होंने उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में इस विचार को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। इसके बाद धीरे धीरे अन्य देशों में निजी करण को स्वीकार करके साकार रूप प्रदान किया। जिन क्रियाओं का या उद्यमों को पूर्व में सरकार द्वारा संचालित या प्रबंधित किया जा रहा है। जब उनको किसी निजी कंपनी या उद्यमी या संस्था को संचालित या प्रतिबंध करने के लिए सौंप दिया जाता है, इस हस्तांतरण की प्रक्रिया को निजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। भारत में निजी करण की प्रक्रिया अभी कुछ वर्ष पूर्व से प्रारंभ हुई है। सामान्य रूप से निजी करण का आशय है -स्वामित्व में परिवर्तन अर्थात सरकारी स्वामित्व की स्थान पर किसी व्यक्ति या कंपनी या व्यवसाय या उद्यमी

का स्वामित्व। राजा हम लोगों में यह धारणा बन गई की निजी करण से निष्पादन में अनिवार्य रूप से सुधार होता है। इसके माध्यम से लागत में कमी और गुणवत्ता को उन्नत बनाया जाता है। वस्तुतः निजीकरण का मूल मंत्र होता है प्रतिस्पर्धा। उसका मुख्य उद्देश्य होता है मुनाफा।

भारत में निजीकरण:-

भारत में निजी करण का प्रश्न व्यापार तथा उद्योगों में प्रवेश कर चुका है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां दुनिया भर में बेरोकटोक व्यापार और कल कारखानों का जाल बिछा रही है और सरकारों ने अपने तमाम बंधन कारी नियमों को निरस्त कर उन्हें कुछ भी करने की छूट दे रखी है। लाइसेंस परमिट राज का अब कोई अता पता नहीं है ।

1. शिक्षा के क्षेत्र में निजी करण ने अपने पैर पसार लिए हैं। आज शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्त पोषित संस्थाओं की भरमार होती जा रही है। इन संस्थानों में शिक्षक प्रशिक्षक को 3 से 5000 से अधिक का वेतन वास्तव में नहीं मिल रहा है। इन संस्थाओं के पास अपने भवन भी नहीं है। हुए किराए के भवनों में चलाए जा रहे हैं। एनआईआई सीटों का बाजारीकरण हो रहा है। सम बंधन के समय कुछ खिलाने पिलाने की आवश्यकता जरूर होती है। **पैसा फेंको तमाशा देखिए**, वाली कहावत यहां चरितार्थ हो रही है।

2. देश में एक तरफ मिशनरियों स्कूल चल रही है तो दूसरी और संघ परिवार सरस्वती शिशु मंदिर केशव सरस्वती स्कूल, शिशु भारतीय शिक्षा भारती के नाम से स्कूल खोल रहा है। दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसायटी विभिन्न नगरों में अपना स्कूल खुलवा रही है जिनमें मनमानी फीस वसूली जाती है। देश का अविभाज्य वर्ग इन्हीं स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। इसके अतिरिक्त **सीबीएसई** तथा **आईसीएस सी** के सिलेबस पढ़ाने वाले स्कूल खुल रहे हैं और पैसे के बलबूते इन्फ्राट्रक्चर निर्मित कर वे सेंट्रल बोर्ड से संबंधित भी प्राप्त कर रहे हैं। सरकार द्वारा संचालित व संपोषित स्कूल आज किस्म- किस्म के स्कूलों में घिरते जा रहे हैं। निजी क्षेत्र में संचालित स्कूलों से उनकी कोई स्पर्धा नजर नहीं आती है। वे उनकी तुलना में निम्न स्तर की देखने को मिलते हैं।

3. निजी स्कूल अपनी छद्म योजनाओं से प्रवेश को कठिन बना कर मांग एवं पूर्ति का खेल खेलती है। साथ ही मनोवैज्ञानिक स्तर से अपने विद्यालय में समाज की क्रीम छाटने का प्रयास करते हैं। निजी संस्थाएं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा निदेशालय से मान्यता प्राप्त करती है। साथ ही उनके नियमों का अधिक से अधिक पालन करती हैं जिसके परिणाम स्वरूप अच्छे भवन, स्वच्छ एवं बड़े बड़े कमरे, शुद्ध पानी की व्यवस्था, अच्छा वातावरण, अच्छा रखरखाव, उद्यान, खेल के मैदान आदि की उपयुक्त व्यवस्था होती है। इनमें पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं की उपयुक्त व्यवस्था होती है। निजी शिक्षण संस्थानों में शिक्षण दिवस भी अधिक होते हैं, क्योंकि वे अन्य सरकारी विद्यालयों की बात राष्ट्रीय एवं राज्य कार्यों, अभियानों, योजनाओं, चुनावों आदि से प्रभावित नहीं होती हैं। यह संस्थाएं सामयिक परत की व्यवस्था अपने स्तर पर करती है जो सप्ताहिक से लेकर मासिक होती हैं। प्रत्येक परख के नाम पर शुल्क भी लिया जाता है। शिक्षक पर काम का बोझ और बढ़ता है। इसके बदले में उसे कुछ नहीं मिलता है। वह अपनी नौकरी को बचाने के लिए आदेशानुसार काम करता रहता है। इन्हीं स्कूलों में अभिभावक स्वयं बालक को पढ़ने पढ़ाने में रुचि लेते हैं। अच्छे ट्यूटर की व्यवस्था कराते हैं। इन सब कारणों से इन विद्यालयों में रिजल्ट अच्छे रहते हैं।

4. भारत में स्ववित्त पोषित कॉलेजों की स्थापना हुई जो कि राज्य विश्वविद्यालयों से संबंध है। यह स्थिति आंशिक निजी करण की है। इस मॉडल में गुणवत्ता का दायित्व विश्वविद्यालय पर रहता है। कई बार कुछ कालेजों ने अपने यहां परीक्षा से नकल करा कर तथा अन्य अनैतिक कार्य करके विश्वविद्यालय की डिग्री का बाजारीकरण किया। ऐसी **घटना नागपुर विश्वविद्यालय** से संबंध कुछ कॉलेजों में घटित हुई। ऐसी घटना प्राइवेट विश्वविद्यालयों में घटित नहीं हो सकती क्योंकि उसे सदैव अपनी बंदी का भय बना रहता है। प्राइवेट विश्वविद्यालयों के मामले में सबसे बड़ा डर इस बात का बना रहता है कि वे अपनी डिग्रियों को बेचने लगेंगे। इस संबंध में प्रोफ़ेसर बी.एम का कहना है कि अमेरिका में ऐसा क्यों नहीं हुआ। क्योंकि विश्वविद्यालय की शैक्षिक अवसरों को संपूर्ण विश्व में एक्रीडिटेशन की वैज्ञानिक विधि से नियंत्रित किया जाने लगा है भारत में **अगस्त 1995 में**

प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल संसद में पेश किया गया। लोकसभा ने इसे पारित कर दिया था। परंतु राज्यसभा ने उसे पारित नहीं किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे हरी झंडी दे दी है। अतः इस बिल को पुनः संसद में प्रस्तुत किया जाए और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में भाग ले।

प्रारंभिक शिक्षा में निजीकरण का प्रभाव:-

यदि प्रारंभिक शिक्षा का निजीकरण किया गया तो लड़कियां शिक्षा से महरूम रह जाएंगीं जबकि सरकार सामाजिक न्याय का ढोल बजाती है ।साथ ही ग्रामीण अंचल के बच्चे भी निजी स्कूलों की महगीं शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ रहेंगे। अतः 6 से 14 आयु वर्गके सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व राज्य का है। अतः उसे इसके लिए अपने विद्यालय स्थापित करने चाहिए। साथ ही गुणवत्ता को सुधारने के लिए कार्य करना चाहिए क्योंकि ऐसा न करने पर वह उनके मौलिक अधिकार से उनको वंचित कर देगी। आज भी अधिकांश भारतीय गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। अतः उनके बीच निजी संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकेंगे। उदाहरण दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसायटी द्वारा स्थापित विद्यालयों में प्रथम कक्षा के बालक से करीब 3000 प्रतिमाह फीस ली जाती है। ग्रामीण अंचल के बालक इन स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ रहेंगे। अतः 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए सरकार द्वारा ही व्यवस्था की जानी चाहिए। इस क्षेत्र में निजी करण को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। सरकार एक ही प्रश्न रखती है की धन का अभाव है। सरकार को यह बहाना नहीं लगाना चाहिए क्योंकि 1992 से 1997 में शिक्षा पर वार्षिक योजना में 3920 करोड़ की धनराशि निर्धारित की थी जबकि 2019 से 2020 में राज्य विद्युत बोर्ड को 10684 करोड रुपए की हानि हुई। जोकि शिक्षा के व्यय का 21 / 2 गुना है। अतः राजनीतिक संकल्प और ग्रीन आस्था होनी चाहिए प्रारंभिक शिक्षा भावी भारत के लिए अनिवार्य निवेश है। अतः हर संभव प्रयास से इसके लिए धनराज की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए दान उद्योग कर आज की व्यवस्था होनी चाहिए। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आंशिक निजी करण की ओर कदम उठाया जा सकता है

। परंतु सरकार उन पर अपना नियंत्रण अवश्य रखें जिससे वह अनैतिक कार्यों से दूर रह सके।

सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा ग्रामीण विकास में निजी निवेश पर नीति प्रारूप तैयार किया जिसमें कहा गया कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी विधेयक तैयार कर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीन प्राइवेट विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए। यह नवीन प्राइवेट विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्रों से संबंधित कोर्स प्रदान करें। प्रो. बीएस नाईक ने निजी करण के सकारात्मक पहलू पर बोल देते हुए लिखा है कि भारत के लिए प्राइवेट विश्वविद्यालय नवीन है। परंतु अमेरिका में एक विश्वविद्यालय सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे हैं। इनकी स्थापना एवं संचालन विभिन्न संस्थाओं चर्च, उद्योग, संगठनों द्वारा किया जाता है। इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर राज्य द्वारा नियंत्रित विश्वविद्यालयों से अधिक अच्छा है। साथ ही इसमें शोध कार्य उनसे अधिक श्रेष्ठ किए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता तथा संख्या की मांग पूर्ति राज्य विश्वविद्यालयों के साथ-साथ प्राइवेट विश्वविद्यालय स्थापित करके की जा रही है।राज विश्वविद्यालय सरकार के अधीन बने हुए हैं। इस कारण वे स्वायत्तता का उपयोग नहीं कर पाती। अतः उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान के स्तर को उन्नत बनाने के लिए प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। प्राइवेट विश्वविद्यालयों में राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए कोई स्थान नहीं है। इनमें कुल पद की नियुक्ति सरकार द्वारा नहीं की जाती। वरुण विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा की जाती है। इन विश्वविद्यालयों में फीस अधिक होती है। क्योंकि यह उच्च स्तर की प्रयोगशाला है पुस्तकालय तथा शिक्षा प्रदान करते हैं। यह संस्थाएं दान स्वरूप बहुत ही धनराशि भी प्राप्त करती है।

भूमंडलीकरण में उच्च शिक्षा:-

आज प्रतीक राष्ट्र में उच्च शिक्षा को विशेष महत्व दिया जा रहा है क्योंकि सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक, विद्वान, साहित्यकार, नेता, कवि, दार्शनिक उच्च शिक्षा के प्रांगण से ही उत्पन्न होते हैं। उच्च कोटि के सत्यान्वेषण के लिए विश्वविद्यालय ही एक ऐसी प्रयोगशाला है जो ज्ञान के क्षेत्र को विस्तृत बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान भी दे सकते हैं।संपूर्ण विश्व की भांति भारत

में भी प्राथमिक शिक्षा को आधारशिला के रूप में तथा उच्च शिक्षा को मुकुट के रूप में शिकार किया गया है। जहां तक भारत में उच्च शिक्षा की व्यवस्था एवं विकास का प्रश्न है तो इसे समानता वैदिक ,बौद्ध, मुस्लिम ,ब्रिटिश तथा स्वतंत्रता के उपरांत के काल क्रम में विभाजित कर विवेचना किया जा सकता है।सफलता के उपरांत भारत में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा से लेकर व्यवसाय शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। और शिक्षा का क्षेत्र न केवल विस्तृत हुआ अपितु बहु आयामी भी हो गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद से ही भारत में शिक्षा संबंधी नीतियों, शिक्षा की संरचना शिक्षण पद्धतियों आज सभी क्षेत्रों में सुधार एवं विकास के लिए अनेक सार्थक प्रयास किए जाते रहे हैं। **शैक्षिक और समानताएं** एवं शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशेष संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाएं भी निर्धारित की गई है। आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक परिपेक्ष में शिक्षा की व्यवहारिकता और उपादेयता को निश्चित करने के लिए समय अनुसार विभिन्न आयोगों और समितियों का गठन, शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्धारण,विभिन्न स्तरों पर शिक्षा में गुणात्मक अभिवृद्धि के लिए विशिष्ट संस्थानों एवं विशिष्ट संस्थानों की स्थापना, वर्ग एवं क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार विशिष्ट कार्यक्रमों, योजनाओं का निर्धारण और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए गए हैं। यदि अतीत की ओर जहां देखा जाए तो पता चलता है कि भारतीय उच्च शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव कोई नया नहीं है। **भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली** पर दृष्टिपात करने से उस पर अंतरराष्ट्रीय प्रभाव के प्रथम स्पर्श को अस्पष्टता अनुभव किया जा सकता है। बात वर्तमान परीक्षा प्रणाली की हो या स्नातक स्तर की शिक्षा की या फिर विश्वविद्यालय स्तर की योजनाओं की ब्रिटिश शिक्षा का प्रभाव सभी पर स्पष्ट लक्षित होता है। **आईआईटी के सभी पैटर्न यूएस के तकनीकी संस्थानों** के पैटर्न पर आधारित हैं। अपनी स्थापना से लेकर आज तक यह संस्थान विदेशों का अभी भी अनुकरण कर रहे हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त अध्ययन केंद्र यूके के ओपन यूनिवर्सिटी की अवधारणा पर आधारित है। यहां तक की रविंद्र नाथ टैगोर जो कि उच्च कोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय तावादी थे। उन्होंने भी पूर्व और पश्चिम का समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से शिक्षा द्वारा अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करने के

लिए विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। बौद्धिक धन सभी के लिए की धारणा को लेकर चलने वाला विश्व भारती पास 7 देशों के लिए ज्ञान के नवीन द्वार खोलता है।अतः **भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण की अवधारणा** अत्यंत प्राचीन है। भूमंडलीकरण अंतरराष्ट्रीय ढांचे पर भारतीय शिक्षा के गठजोड़ समन्वय का नाम है। इस दोहरी शिक्षा ने बहुआयामी बनने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा स्तर के अतिरिक्त अनेक सीमाओं को पार कर लिया है।वैश्विक रूप से व्यवस्थित होने के लिए शिक्षा का संसार निरंतर सिमट ता जा रहा है और इस क्षेत्र में वैश्वीकरण की अवधारणा परंपरा और आधुनिकता के बीच सेतु का काम करती दिखाई देती है।

वैश्वीकरण और शिक्षण संस्थान :-

वैश्वीकरण के दौर में विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय,चिकित्सालय प्राथमिक शिक्षा केंद्र तक स्वतंत्र बाजार से संबंध हो गए हैं। इन सब के स्थानीय प्रबंधन ने इन संस्थाओं को कारोबार का स्वरूप दे डाला और यह अनुमान लगाया कि विद्यालय और विश्वविद्यालयों के मध्य की प्रतियोगिता अधिक योग्यता और क्षमता को उत्पन्न करेगी और विद्यार्थियों के सामने ढेरों विकल्प पैदा हो जाएंगे इन स्थितियों ने शिक्षा और बाजार के बीच मजबूत संबंध बनाए। विकास की प्रक्रिया ने सरकार और शिक्षण के मध्य तनाव को जन्म दिया।क्योंकि शिक्षा एक मात्र ऐसा पेशा है जो सरकार के विरुद्ध आलोचना को न केवल वैचारिक आधार देता है, अपितु उसे जन्नत का रूप दे देता है।इसलिए हर बार सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नियंत्रण की स्त्रियों को उत्पन्न करती है।

निष्कर्ष:-

भारत जैसे विशाल देश में शिक्षा की समुचित व्यवस्था कर पाना सरकार के लिए एक नितांत कठिन कार्य रहा है। देश की एक अरब 40 करोड़ जनसंख्या को पूर्वोत्तर शिक्षित कर पाने के लिए न तो सरकार के पास पर्याप्त आर्थिक साधन है, और ना ही उसके लिए पर्याप्त प्रबंध की सुविधाएं उपलब्ध है ।हमारे देश में शिक्षा केंद्रीय समवर्ती सूची में न वह कर राज्यो का विषय हैअर्थात शिक्षा उपलब्ध का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का न होकर राज्य सरकारों का है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. अग्रवाल प्रो.एम.डी. भारत में वित्तीय प्रबंधन पंचशील प्रकाशन जयपुर 2013 पृष्ठ 5 से 39 .
2. माहेश्वरी डॉक्टर पीडी गुप्ता ,डॉ एस सी गुप्ता, मौद्रिक अर्थशास्त्र एवं बैंकिंग कैलाश पुस्तक सदन भोपाल पृष्ठ 252 से 255 .
3. मिश्रा एवं डॉ पंत, बेस्ट अर्थशास्त्र साहित्य भवन पब्लिकेशन।
4. नागर डॉ विष्णु दत्त, डॉक्टर मेहता बल्लभ, भारतीय अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी पृष्ठ 16 से 18 .
5. शर्मा विरेंद्र प्रकाश, प्रकाश रिसर्च मेथोलाजी पंचशील प्रकाशन जयपुर 2012 पृष्ठ 6 से 35।
6. सिन्हा डॉक्टर बी सी मुद्रा बैंकिंग विदेशी विनिमय तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार लोकभारती प्रकाशन सन 1980 पोस्ट 16 से 18 .